दैनिक भारत कि
तामीर
संपादक - काझी मकदूम शफीउद्दीन hinditameer@gmail.com
Editor in chief- Qazi makhdoom shafiuddin

बीड (महाराष्ट्र) | वर्ष-१ ला | अंक-३५० वा | बुधवार ३० जुलै २०२५ | RNI TITLE CODE:MAHHIN11405/120/1/3/2024 | किमत : २ रूपये | पन्ने - ४

वाल्मिक कराड की संपत्ति जब्त कर एसआईटी से जांच कराई जाए-विधायक रोहित पवार की मांग

परळी वैजनाथ, २९ जुलाई (प्रतिनिधि)

विधायक रोहित पवार ने मांग की है कि वाल्मिक कराड की एक हजार करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त कर, विशेष जांच टीम (एसआईटी) गठित करके संपत्ति की गहन जांच कराई जाए। वे परळी में महादेव मुंडे के परिवार से मुलाकात के बाद मीडिया से बात कर रहे थे।

उन्होंने बताया कि महादेव मुंडे की पत्नी ज्ञानेश्वरी मुंडे की मांग के अनुसार संतोष साबळे और पंकज कुमावत को एसआईटी में शामिल किया जाए, इस संबंध में उन्होंने उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से भी निवेदन किया है।

परळी दौरे के दौरान विधायक रोहित पवार ने पुलिस अधीक्षक नवनीत कॉवत से संपर्क कर इस प्रकरण की जानकारी भी ली।

मंगलवार (२९ जुलाई) को शाम करीब ५ बजे विधायक रोहित पवार, विधायक संदीप क्षीरसागर, राजेंद्र मस्के, राजेसाहेब देशमुख और राजाभाऊ फड ने महादेव मुंडे के परिवार से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने महादेव मुंडे की हत्या के मामले की विस्तृत जानकारी ली। मुलाकात के समय महादेव मुंडे की पत्नी ज्ञानेश्वरी मुंडे और उनके रिश्तेदार सतीश फड ने रोहित पवार को बताया कि हत्या किस प्रकार हुई और किन-किन लोगों के नाम इस मामले में सामने आए हैं। इसके बाद विधायक रोहित पवार ने पुलिस अधीक्षक नवनीत कॉवत से संपर्क कर जांच की प्रगति के संबंध में चर्चा की।

राहुल गांधी ने 'ऑपरेशन सिंदूर' को बताया प्रधानमंत्री की छवि बचाने की कोशिश, पीएम मोदी का जवाब- हमने पाकिस्तान पर सीधा हमला किया

नई दिल्ली। २९ जुलाई २०२५। विशेष संवाददाता

लोकसभा में चल रहे मानसून सत्र के दौरान 'ऑपरेशन सिंदूर' को लेकर सरकार और विपक्ष आमने-सामने आ गए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि यह सैन्य कार्रवाई देश की सुरक्षा के बजाय प्रधानमंत्री की छवि को बचाने के लिए की गई थी। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा, अगर ट्रंप झूठ बोल रहा है तो मोदी को संसद में खड़े होकर कहना चाहिए कि ट्रंप झूठा हैद्द

राहुल गांधी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान का हवाला दिया जिसमें उन्होंने दावा किया था कि उन्होंने भारत-पाकिस्तान संघर्ष में हस्तक्षेप कर युद्ध को रोका। राहुल ने सवाल उठाया कि अगर ट्रंप ने २९ बार यह बात कही और वह झूठा है, तो प्रधानमंत्री मोदी क्यों चुप हैं। उन्होंने कहा कि ट्रंप के दावे झूठे हैं और प्रधानमंत्री को उसे खुलकर खारिज करना चाहिएद्द

राहुल ने यह भी आरोप लगाया कि ऑपरेशन के दौरान पायलटों को दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम पर हमला करने की इजाजत नहीं दी गई थी। उन्होंने कहा कि सेना के पायलटों के हाथ बांध दिए गए थे और इस ऑपरेशन को सीमित रखने के निर्देश राजनीतिक नेतृत्व से आए थे।

प्रधानमंत्री मोदी ने जवाब देते हुए कहा कि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ निर्णायक हमला किया और किसी भी देश ने इस कार्रवाई को रोकने की मांग नहीं की। उन्होंने कहा कि यह हमला आतंक के खिलाफ था और ९ मई को भारत ने पाकिस्तान के सैन्य और आतंकी ठिकानों

पर सीधा प्रहार किया। मोदी ने कहा, हमने पाकिस्तान के सीने पर हमला किया।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर केवल २२ मिनट चला और इसके बाद पाकिस्तान से संपर्क कर भारत ने कहा कि हम और तनाव नहीं चाहते। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि भारतीय वायुसेना की कार्रवाई योजनाबद्ध और संयमित थी, ताकि तनाव न बढ़े।

गृह मंत्री अमित शाह ने भी राहुल गांधी पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस अपने ही विदेश मंत्री पर भरोसा नहीं करती, लेकिन ट्रंप जैसे विदेशी नेताओं के बयानों पर भरोसा करती है। उन्होंने कहा कि यह कांग्रेस की विदेश नीति की गंभीर कमजोरी को दर्शाता है।

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने ट्रंप के बयानों को पूरी तरह खारिज करते हुए कहा कि अमेरिका या किसी अन्य देश ने भारत को इस ऑपरेशन को रोकने के लिए नहीं कहा था। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यापारिक या कूटनीतिक दबाव भारत की सैन्य नीति को प्रभावित नहीं करता।

गृह मंत्री ने संसद में ऑपरेशन 'महादेव' की भी जानकारी दी, जिसमें तीन लश्कर-ए-तैयबा आतंकियों को जम्मू-कश्मीर में मार गिराया गया था। उन्होंने यह भी बताया कि भारत की खुफिया एजेंसियां सतर्क हैं और हर मोर्चे पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है।

राहुल गांधी ने जवाब में कहा कि उन्होंने विपक्ष की ओर से सरकार को समर्थन देने के बावजूद यह महसूस किया कि सरकार ने सेना की बहादुरी का इस्तेमाल अपनी प्रचार छवि को चमकाने के लिए किया। उन्होंने कहा कि सेना देश की है, किसी राजनीतिक दल की नहीं।

प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि भारत अपनी संप्रभुता के साथ कोई समझौता नहीं करता और देश की सुरक्षा के लिए हर कदम सोच-समझकर उठाया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत ने जब हमला किया, तब ही युद्धविराम की बात मानी, ताकि संदेश स्पष्ट जाए कि भारत कमजोरी नहीं, मजबूती से जवाब देता है।

यह बहस न केवल संसद बल्कि देशभर में चर्चा का विषय बन गई है, जहां जनता और विश्लेषक अब यह सवाल कर रहे हैं कि क्या सुरक्षा नीतियां राजनीतिक छवि से प्रभावित हो रही हैं या वाकई में राष्ट्रीय हित सर्वोपरि हैं।

कुरैशी समाज पर हो रहे अन्याय के खिलाफ कानूनी संरक्षण की मांग को लेकर जिलाधिकारी को सौंपा गया ज्ञापन

रिपोर्ट: काज़ी अमान / बीड

कुरैशी समाज पर हो रहे अन्याय के खिलाफ न्याय और कानूनी संरक्षण की मांग को लेकर जमीयतुल कुरैश बीड जिला एवं समस्त कुरैशी समाज की ओर से एक प्रतिनिधिमंडल ने मुफ्ती अब्दुल्ला कुरैशी और संगठन के अध्यक्ष हाजी अब्दुल जब्बार कुरैशी के नेतृत्व में जिलाधिकारी विवेक जॉनसन से मुलाकात की और उन्हें एक लिखित ज्ञापन सौंपा।

ज्ञापन में कहा गया है कि कुरैशी समाज पारंपरिक रूप से कानून का पालन करते हुए भैंस व बैल जैसे कृषि पशुओं की खरीद-फरोख्त से जुड़े व्यवसाय में संलग्न है। समाज के सभी व्यापारी कृषि उत्पन्न बाजार समिति से प्रमाण-पत्र, परिवहन अनुमति, पशु-चिकित्सकीय जांच प्रमाण-पत्र आदि सभी आवश्यक दस्तावेज महाराष्ट्र शासन के नियमों के तहत नियमित रूप से प्राप्त करते हैं और सभी प्रक्रियाएं कानूनी ढंग से पूरी करते हैं।

लेकिन हाल ही के दिनों में कुछ संगठनों और व्यक्तियों द्वारा समाज पर

जबरन और उग्र पद्धति से अन्याय किया जा रहा है। हमारे समाज के व्यापारियों को रास्तों में रोककर जातिसूचक और अश्लील गालियाँ दी जा रही हैं, उनके साथ मारपीट और मॉबलिंचिंग जैसी गंभीर घटनाएं घट रही हैं।

इन घटनाओं के मद्देनज़र बीड जिले के सभी कुरैशी समाजबंधुओं ने एकमत होकर फैसला लिया है कि वे सभी प्रकार के पशु बाजार बंद करेंगे और किसी भी प्रकार के पशु की खरीद-फरोख्त नहीं करेंगे। इस निर्णय के कारण महाराष्ट्र के किसानों और व्यापारियों को भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है। उल्लेखनीय बात यह है कि मांस निर्यात से जुड़ी कंपनियां भी बंद होने की कगार पर हैं, जिससे राज्य के राजकोष को बड़ा नुकसान पहुंच रहा है। विशेष रूप से यह ध्यान देने योग्य है कि भारत दुनिया में बीफ निर्यात करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश है। लेकिन अगर कुरैशी समाज पर अत्याचार इसी तरह चलता रहा और उनकी मांगें नहीं मानी गईं तो समाज अपनी व्यावसायिक गतिविधियां बंद रखेगा।

कुरैशी समाज की प्रमुख मांगें इस प्रकार हैं:१. आर्थिक व्यवहारों में पारदर्शिता के लिए एपीएमसी (कृषि उत्पन्न बाजार समिति) में ऑनलाइन प्रणाली अनिवार्य की जाए। २. पूरे राज्य में सेस शुल्क एक समान किया जाए और व्यापारी लाइसेंस समय पर वितरित किए जाएं।

३. परिवहन परमिट का त्वरित ऑनलाइन वितरण किया जाए। ४. प्रत्येक स्थानीय स्तर पर सरकारी स्लॉटर हाउस (वधगृह) की स्थापना की जाए। ५. कोंडवाडा जैसी सुविधाएं विभागानुसार तुरंत शुरू की जाएं। ६. अवैध और बिना अनुमति चल रहे गौशाला केंद्रों को तत्काल बंद किया जाए। ७. कथित गौरक्षकों के खिलाफ सख्त नियमावली तैयार की जाए। ८. कुरैशी समाज के लिए अलग आर्थिक विकास महामंडल स्थापित किया जाए। इन सभी मांगों पर गंभीरता से विचार करते हुए किसानों और कुरैशी समाज पर हो रहे अन्याय को समाप्त किया जाए और उन्हें उचित कानूनी संरक्षण प्रदान किया जाए, ऐसी मांग ज्ञापन में की गई है। ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वालों में हाजी अब्दुल जब्बार मुहम्मद कुरैशी, मुहम्मद रफीक इब्राहीम कुरैशी, हाजी जावेद अब्दुल खालिक कुरैशी, मुहम्मद साजिद मोहम्मद कुरैशी, मौलाना नाजेर, हाफिज नादिर, हाफिज अब्दुल खय्यूम, हाफिज सलीम, मुहम्मद हारून, अली हुसैन, अब्दुल मुजीब, मुहम्मद शाहिद आदि के नाम शामिल हैं।

गृह राज्य मंत्री के खिलाफ सबूत दिए जाने पर मुख्यमंत्री को उनसे इस्तीफ़ा लेना चाहिए: अनिल परब की मांग

रिपोर्ट: जमीर काज़ी। मुंबई

ठाकरे गुट के नेता और विधायक अनिल परब ने मंगलवार को कहा कि महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री योगेश कदम की माता के नाम से एक डांस बार चलाया जा रहा है और वे अवैध रेत खनन में भी लिप्त हैं। इस संबंध में उन्होंने पहले जो आरोप लगाए थे, उनके सभी सबूत आज उन्होंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को सौंप दिए हैं। अब मुख्यमंत्री को चाहिए कि वे योगेश कदम से इस्तीफ़ा लें, ऐसी मांग परब ने की।

विधानमंडल के पावसाळी सत्र के दौरान परब ने मंत्री योगेश कदम पर डांस बार और रेत तस्करी से संबंधित गंभीर आरोप लगाए थे। मंगलवार को मुख्यमंत्री से मुलाक़ात कर उन्होंने इससे जुड़े तमाम दस्तावेज, वीडियो और सबूत सौंपे। इसके बाद पत्रकारों से बात करते हुए परब ने कहा,

मुख्यमंत्री ने सभी सबूतों की जांच कर उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है।

परब ने बताया कि,

पावसाळी सत्र के अंतिम दिन मैंने समतानगर में 'सावली डांस बार' का मुद्दा उठाया था, जो गृह राज्य मंत्री योगेश कदम की मातोश्री के नाम पर चलाया जा रहा है। इससे महाराष्ट्र सरकार की छवि धूमिल हो रही है। मैंने जो आरोप लगाए थे, उनके समर्थन में सारे प्रमाण दिए हैं। अब मुख्यमंत्री को उन्हें परखना चाहिए।

उन्होंने यह भी बताया कि इस डांस बार पर

१० अगस्त २०२३,
२८ मई २०२४,
और ३१ मई २०२५ को
पुलिस ने छापेमारी की थी, जिसमें
२२ बार बालाएं,
२२ ग्राहक,
और नकद राशि जब्त की गई थी।

यह अपराध बार-बार हो रहा है और पुलिस के रिकॉर्ड में दर्ज भी है। कानून के अनुसार, डांस बार से जुड़े किसी भी गैरकानूनी कार्य की जिम्मेदारी मूल मालिक की होती है। इसलिए मंत्री से इस्तीफा लिया जाना चाहिए।

अवैध रेत खनन पर भी परब ने कहा,

अवैध रेत को खेड स्थित योगिता डेंटल कॉलेज में डंप किया गया है। इस खनन में अकित मुकादम नामक कार्यकर्ता शामिल है और परिवहन विभाग का एक अधिकारी ई-चलन मशीन का दुरुपयोग कर वसूली कर रहा है। इसके वीडियो फुटेज भी सौंपे गए हैं।

परब ने आगे बताया,

इस अवैध रेत खनन पर उच्च न्यायालय ने शो कॉज़ नोटिस जारी कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। अदालत का वह आदेश भी प्रमाण के तौर पर मुख्यमंत्री को सौंपा गया है।

अंत में उन्होंने कहा,

मुख्यमंत्री को अब इन सबूतों की जांच कर ठोस निर्णय लेना चाहिए।

अल्पसंख्यक छात्रों के लिए विदेश में पढ़ाई हेतु छात्रवृत्ति

ऑनलाइन आवेदन १ अगस्त तक करें-जे.डी. शाह का आह्वान

बीड, प्रतिनिधि:

महाराष्ट्र राज्य के अल्पसंख्यक विकास विभाग की ओर से अल्पसंख्यक समुदाय के मुस्लिम, बौद्ध, ईसाई, जैन, पारसी, यहूदी और सिख छात्रों से वर्ष २०२५-२६ के लिए विदेश में उच्च शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति के ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं।

इस योजना का लाभ लेने के लिए छात्र महाराष्ट्र का निवासी तथा उपरोक्त अल्पसंख्यक समुदाय से होना चाहिए।

पोस्ट ग्रेजुएशन पाठ्यक्रम के लिए अधिकतम आयु ३५ वर्ष तथा

पीएच.डी. के लिए ४० वर्ष तय की गई है।

अभ्यर्थी के परिवार की वार्षिक आय ८ लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

दो वर्ष की अवधि में एमबीए पाठ्यक्रम को भी इस योजना में मान्य किया गया है।

बीड जिले के मुस्लिम छात्रों से अपील करते हुए समाजसेवक जे.डी. शाह ने कहा कि इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाकर विदेश में शिक्षा प्राप्त करने का सपना पूरा करें और १ अगस्त २०२५ तक ऑनलाइन आवेदन अवश्य करें।

प्रेस विज्ञप्ति में आगे कहा गया है कि-

छात्रवृत्ति की कुल सीटों में से ३०% सीटें छात्राओं के लिए आरक्षित रहेंगी, चयन मेरिट के आधार पर होगा।

एक ही परिवार के अधिकतम दो बच्चों को ही इस योजना का लाभ दिया जाएगा।

पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या डिप्लोमा के लिए ग्रेजुएशन में और पीएच.डी. के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन में कम से कम ५५% अंक आवश्यक हैं।

डिग्री/डिप्लोमा परीक्षा पास होना अनिवार्य है और यह आवेदन की तारीख तक पूरा हो चुका होना चाहिए।

योजना के अंतर्गत मान्य विदेशी विश्वविद्यालयों को लेकर भी निर्देश दिए गए हैं:

आवेदनकर्ता को टड वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में टॉप २०० में आने वाले संस्थान में प्रवेश लेना अनिवार्य होगा।

छात्र को हर सेमेस्टर या छह महीने में पास होना आवश्यक है और यूनिवर्सिटी द्वारा प्रमाणित मार्कशीट, प्रगति रिपोर्ट, प्रमाणपत्र आदि अनिवार्य रूप से जमा करने होंगे।

छात्रवृत्ति के अंतर्गत मिलने वाले लाभ:

विदेश के संस्थान द्वारा बताए गए पूरा ट्यूशन फीस,

पाठ्यक्रम के लिए नजदीकी मार्ग से एयर टिकट का खर्च (आवागमन दोनों सहित),

निवास भत्ता,

पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस का खर्च आदि का भुगतान सीधे छात्र के बैंक खाते में भारतीय रुपयों में प्रतिपूर्ति के रूप में किया जाएगा।

इसके लिए सभी मूल दस्तावेजों की जाँच की जाएगी - फीस रसीद, एयर टिकट की रसीदें, बोर्डिंग पास आदि।

आवेदन प्रक्रिया:

आवेदन का प्रारूप और विस्तृत जानकारी के लिए ु.ारहरीलहेश्ररीहळ.सिीं.ळप की वेबसाइट के ताजा घडामोडी लिंक पर जाएं।

आवेदन फॉर्म डाउनलोड कर सभी आवश्यक दस्तावेजों सहित ऑनलाइन भरें और उसकी प्रिंट कॉपी समाज कल्याण आयुक्तालय, ३ चर्च रोड, पुणे - ४११००१ को डाक द्वारा या स्वयं जाकर जमा करें।

साथ hr, https://fs.mahascholarship. gov.in पोर्टल पर भी जानकारी भरना अनिवार्य है।

समाजसेवक जे.डी. शाह ने अल्पसंख्यक छात्रों से इस योजना का लाभ उठाने का आह्वान किया है।

उर्दू दैनिक तामीर के २५ वो साल में क़दम रखने पर एक और पेशकश

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के बीड़ तालुका अध्यक्ष पद पर ॲड. राजेंद्र राऊत की नियुक्ति

राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व मंत्री विधायक धनंजय मुंडे ने सौंपा नियुक्ति पत्र

बीड़ (प्रतिनिधि), २९ जुलाई:

तालुका के नाळवंडी गांव के सरपंच और जिला परिषद के पूर्व सदस्य ॲड. राजेंद्र राऊत को मंगलवार (२९ जुलाई) को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के बीड़ तालुका अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया। यह नियुक्ति मुंबई में एक छोटे कार्यक्रम के दौरान हुई, जिसके बाद पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं द्वारा उन्हें बधाइयाँ दी जा रही हैं।

इस नियुक्ति की घोषणा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राज्य के उपमुख्यमंत्री और बीड़ जिले के पालक मंत्री विधायक अजित दादा पवार, तथा प्रदेशाध्यक्ष सांसद सुनील तटकरे के निर्देशानुसार की गई।

मुंबई में आयोजित समारोह में राष्ट्रवादी कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व मंत्री विधायक धनंजय मुंडे, प्रदेश महासचिव और पूर्व विधायक अमरसिंह पंडित, जिलाध्यक्ष ॲड. राजेश्वर चव्हाण, और बीड़ विधानसभा अध्यक्ष डॉ. योगेश क्षीरसागर की उपस्थिति में ॲड. राजेंद्र राऊत को नियुक्ति पत्र सौंपा गया।

इस अवसर पर जिला महासचिव बाबासाहेब घुगे, नवगण शिक्षण संस्था के संचालक आमेर सिद्दीकी, पूर्व नगरसेवक बाळासाहेब गुंजाळ, प्रदीप गायकवाड सहित कई पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित थे।

अपनी नियुक्ति पर प्रतिक्रिया देते हुए नवनियुक्त तालुका अध्यक्ष ॲड. राजेंद्र राऊत ने कहा –

पार्टी ने जो विश्वास मुझ पर जताया है, वह सिर्फ सम्मान की बात नहीं बल्कि बीड़ तालुका में संगठन निर्माण की जिम्मेदारी भी है। मैं इसके लिए पार्टी नेतृत्व और जिला के सभी वरिष्ठ नेताओं का आभार प्रकट करता हूं। इस विश्वास को मैं जरूर निभाऊंगा।

उन्होंने आगे कहा –

ग्राम स्तर तक पार्टी की नीतियों और विचारधारा को पहुंचाना, नए नेतृत्व को आगे लाना और कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार करना मेरी प्राथमिकता होगी। आम जनता के मुद्दों पर आवाज उठाना और हर जरूरतमंद की मदद के लिए आगे रहना मेरी कार्यशैली रहेगी।

धानोरा रोड की बदहाली पर नागरिकों का अनोखा 'लोटांगण' आंदोलन

बीड, २९ जुलाई (प्रतिनिधि):

शहर के धानोरा रोड की हालत अत्यंत खराब हो गई है। जगह-जगह बड़े-बड़े गड्ढे बन चुके हैं, लेकिन नगरपालिका प्रशासन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। इसी के विरोध में मंगलवार (२९ जुलाई) दोपहर को साहस आदोडे, नितेश उपाध्ये और क्षेत्र के नागरिकों ने सड़क पर मौजूद गड्ढों के पानी में लोटांगण (पैरों के बल लेट कर पूजा जैसी स्थिति में आंदोलन) लेकर अनोखा आंदोलन किया।

नगर रोड से पालवण चौक (धानोरा रोड) तक लगभग १.७५ किलोमीटर की सड़क पर जगह-जगह बड़े गड्ढे बन गए हैं।

इसी प्रकार मदर तेरेसा चौक से अंकुश नगर मेन रोड, विठ्ठल चौक तक की सड़क भी बेहद जर्जर हो चुकी है।

इतने खराब हालात के बावजूद जब नगरपालिका प्रशासन ने कोई संज्ञान नहीं लिया, तो साहस आदोडे, नितेश उपाध्ये समेत क्षेत्र के नागरिकों ने गड्ढों में लोटांगण लेकर विरोध प्रदर्शन किया और नगरपालिका के खिलाफ नारे लगाए।

नगरपालिका हाय-हाय के नारे लगाते हुए आंदोलनकारियों ने सीधे गड्ढों में बैठकर आंदोलन किया। इसी तरह, नगर रोड, पालवण चौक, छत्रपति शिवाजी महाराज चौक से बशीरगंज, राजुरीवेस, और जुना बाजार तक की सड़कों पर भी भारी मात्रा में गड्ढे बन गए हैं।

आंदोलनकारियों ने आरोप लगाया कि नगरपालिका ने गड्ढे भरने के बजाय जनता को ही गड्ढों में उतरने की नौबत ला दी है।

बीड शहर में हर कोई नगरपालिका की नाकामी पर नाराजगी जाहिर कर रहा है, लेकिन फिर भी प्रशासन आंखें मूंदे बैठा है।

क्या नगरपालिका ने अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लिया है? – ऐसा सवाल अब शहरवासियों में उठने लगा है।

१५९ करोड़ की नगर रोड पर घटिया निर्माण कार्य का खुलासा; महज ४ महीनों में उभर आए गड्ढे!

गुणवत्ता पर सवाल; मरम्मत कर मामला दबाने की कोशिश, जांच और कार्रवाई की मांग-डॉ. गणेश ढवळे

बीड, २९ जुलाई:

बीड शहर के प्रमुख शासकीय कार्यालयों को जोड़ने वाली नगर रोड की २४.५ किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण कार्य जून २०२४ में शुरू हुआ था। लगभग १५९ करोड़ रुपये की लागत से यह कार्य अंतिम चरण में पहुंच चुका है, लेकिन अब तक पूरी तरह से पूरा भी नहीं हुआ कि महज चार महीनों में ही यह सड़क धंसने लगी है और कई स्थानों पर बड़े-बड़े गड्ढे दिखाई देने लगे हैं।

खासकर जिलाधिकारी कार्यालय के सामने सड़क पर गड्ढे उभर आने से नागरिकों में जबरदस्त आक्रोश फैल गया है। प्रशासन ने तात्कालिक रूप से मरम्मत कर मामला शांत करने की कोशिश की है, लेकिन निर्माण की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।

इस मामले में सामाजिक कार्यकर्ता डॉ. गणेश ढवळे (लिंबागणेशकर) ने जिलाधिकारी बीड और महाराष्ट्र राज्य महामार्ग प्राधिकरण के कार्यकारी अभियंताओं को लिखित शिकायत दी है, जिसमें दोषियों पर सख्त कार्रवाई और गहन जांच की मांग की गई है। साथ ही, यदि कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन करने की चेतावनी भी दी गई है।

यह सड़क निर्माण कार्य राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (छक-ख) के अंतर्गत साकेत कंस्ट्रक्शन कंपनी को सौंपा गया था, और दिसंबर २०२४ इसकी तय समय-सीमा रखी गई थी। लेकिन कार्य समय पर पूरा न होने के चलते अब इसे नवंबर २०२५ तक बढ़ा दिया गया है।

कार्य में हुई देरी को लेकर तत्कालीन जिलाधिकारी अविनाश पाठक ने साकेत कंस्ट्रक्शन कंपनी पर १ करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया था। इसके बावजूद न तो निर्माण कार्य की गति में कोई सुधार हुआ और न ही गुणवत्ता में।

यह शहर की सबसे महत्वपूर्ण सड़क है, जो शासकीय कार्यालयों और नागरिक आवाजाही का मुख्य मार्ग है। इसके केवल चार महीनों में ही धंसने लगने से प्रशासनिक तंत्र को भी झटका लगा है। प्रशासन द्वारा की गई मरम्मत को घटिया निर्माण को छिपाने की नाकाम कोशिश बताते हुए डॉ. गणेश ढवळे ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और गहराई से जांच की मांग की है। अन्यथा, उन्होंने आंदोलन की चेतावनी भी दी है।

श्रीनगर का नाम शहीद औरंगजेब नगर', पुणे का नाम महात्मा फुले नगर' और नागपुर का नाम आंबेडकर नगर' रखा जाए - लोकसेना की नरेंद्र मोदी, देवेंद्र फडणवीस और उमर अब्दुल्ला से मांग

रिपोर्ट: बीड प्रतिनिधि

लोकसेना संगठन के प्रमुख ॲड. प्रा. इलियास इनामदार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को एक ज्ञापन भेजकर लोकसेना की ओर से यह मांग की है कि –

पुणे का नाम महान समाजसुधारक क्रांतिसूर्य महात्मा ज्योतिबा फुले के नाम पर महात्मा फुले नगर' रखा जाए,

नागपुर का नाम भारतीय संविधान के शिल्पकार भारत रत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर के नाम पर आंबेडकर नगर' रखा जाए,

और जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर का नाम शौर्य चक्र से सम्मानित शहीद औरंगजेब के नाम पर शहीद औरंगजेब नगर' रखा जाए।

ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि शहीद औरंगजेब, जो भारतीय सेना की ४४ राष्ट्रीय राइफल्स में तैनात थे, ने पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों के सफाए के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। उनकी वीरता को स्मरण में रखने के लिए श्रीनगर का नाम शहीद औरंगजेब नगर' रखा जाना देश के सभी शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

ज्ञापन में यह भी बताया गया कि शहीद औरंगजेब की शहादत के बाद उनकी मां ने भावुक होकर कहा था – अगर मेरे और बेटे होते, तो मैं उन्हें भी देश की सेवा में भेजती।

यह कथन शहीद की मां की देशभक्ति की भावना को दर्शाता है। देश के सैनिक दिन-रात देश की रक्षा करते हैं। यदि उनके नाम पर शहरों के नाम रखे जाएं, तो युवाओं को प्रेरणा मिलेगी और वे उनकी वीरगाथा को याद रखेंगे।

इस संबंध में लोकसेना ने भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार और जम्मू-कश्मीर सरकार से आधिकारिक रूप से यह मांग की है।

धारूर स्थित देवस्थान इनामी जमीन प्रकरण का जिम्मेदार कौन?

वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष समीर काज़ी इस पर ध्यान दें – सैय्यद सलीम बापू की मांग

बीड / प्रतिनिधि

जिले भर में देवस्थान से संबंधित इनामी जमीनों की अवैध खरीद-फरोख्त में लिप्त भूमाफियाओं का एक गिरोह सक्रिय है, जो राजस्व विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत से अवैध रूप से फेरबदल कर जमीन हड़पने की घटनाओं को अंजाम दे रहा है। ऐसा ही एक मामला धारूर शहर में भी सामने आया है।

धारूर में मंदिर, मस्जिद, दरगाह, ईदगाह, अशूरखाना और कब्रिस्तान जैसी धार्मिक संस्थाओं के नाम पर महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड के अंतर्गत आने वाली बड़ी मात्रा में इनामी जमीनें मौजूद हैं। इन जमीनों पर स्थानीय नेताओं और भूमाफियाओं की नजर है। आरोप है कि इन लोगों ने धारूर के तहसीलदार, मंडल अधिकारी, तलाठी और अन्य राजस्व कर्मचारियों के साथ-साथ धारूर नगर परिषद के अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत से अवैध फेरबदल (फर्ज़ी एन.ए. ले-आउट इत्यादि) कर इन जमीनों पर कब्जा करने का षड्यंत्र रचा है।

इस पूरे प्रकरण को लेकर आंबेडकरी विचार मोर्चा और तहरीक-ए-इनाम संगठन की ओर से समय-समय पर वरिष्ठ अधिकारियों को ज्ञापन सौंपे गए थे। यहां तक कि इस मुद्दे पर एक जांच समिति भी गठित की गई थी, लेकिन आज तक उस समिति ने क्या जांच की और क्या निष्कर्ष निकाले, इसका कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। इस जमीन घोटाले को उजागर करने वालों पर दबाव बनाने के लिए, कुछ महिलाओं के माध्यम से झूठे आरोपों और शिकायतों को दर्ज कराने के प्रयास स्थानीय नेताओं और भूमाफियाओं द्वारा किए जा रहे हैं। ऐसे में बीड के पुलिस अधीक्षक और धारूर के पुलिस निरीक्षक को इस गंभीर मामले पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। धारूर के तहसीलदार और अन्य राजस्व अधिकारियों पर वरिष्ठ अधिकारियों का कोई नियंत्रण नजर नहीं आता। हालात ऐसे बन गए हैं कि जो तहसीलदार कहे, वही कानून जैसा माहौल बन गया है। धारूर में बड़े पैमाने पर देवस्थान की इनामी जमीनों के साथ-साथ सरकारी चरागाह (गायरान) जमीनों में भी अवैध फेरबदल और अवैध खरीद-फरोख्त के मामले सामने आए हैं।

तो आखिर धारूर के देवस्थान इनामी जमीन घोटाले का जिम्मेदार कौन है? इस पूरे मामले पर महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष समीर काज़ी को तुरंत ध्यान देकर जांच करानी चाहिए और संबंधित दोषी अधिकारियों, कर्मचारियों व भूमाफियाओं पर वक्फ अधिनियम १९९५ की धारा ५२(१)(अ) के अंतर्गत अपराध दर्ज किए जाने चाहिए।

यह मांग आंबेडकरी विचार मोर्चा के मराठवाड़ा अध्यक्ष सैय्यद सलीम बापू ने एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से की है।

एक शाम मोहम्मद रफ़ी साहब के नाम गीत-संगीत का नि:शुल्क कार्यक्रम

श्रोताओं से बड़ी संख्या में शामिल होने की अपील-एम.एम. शेख, एस.एम.यूसुफ

बीड (प्रतिनिधि):

आगामी ३१ जुलाई को प्रसिद्ध पार्श्वगायक मोहम्मद रफ़ी की पुण्यतिथि के अवसर पर एक शाम मोहम्मद रफ़ी साहब के नाम शीर्षक से एक नि:शुल्क गीत-संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया गया है।

आयोजक व गायक एम.एम. शेख और स्वतंत्र पत्रकार एस.एम. यूसुफ ने श्रोताओं से इस सांगीतिक संध्या में बड़ी संख्या में उपस्थित होने की अपील की है।

यह कार्यक्रम पीस बुक डिपो के संचालक, गायक एवं आयोजक एम.एम. शेख हर वर्ष की तरह इस बार भी प्रस्तुत कर रहे हैं। उनके साथ प्रियंका भंडारी, आकाश जाधव, संध्या जाधव, निशा उजगरे, शेख मझहरुद्दीन, और सैयद मुजीब जैसे गायक-गायिकाएं अपनी प्रस्तुति देंगे।

एम.एम. शेख कई वर्षों से लगातार मोहम्मद रफी की पुण्यतिथि पर यह कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। इस कार्यक्रम को हर वर्ष श्रोताओं का भरपूर प्रतिसाद मिलता है और इसकी लोकप्रियता दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है।

विशेष बात यह है कि इस कार्यक्रम में शामिल सभी गायक बिना किसी पारिश्रमिक के प्रस्तुति देते हैं और इस माध्यम से दिवंगत मोहम्मद रफी को संगीतमयी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।

इस वर्ष भी यह सदाबहार गीतों से सजा नि:शुल्क कार्यक्रम

गुरुवार, ३१ जुलाई २०२५ को

शाम ६:३० बजे,

होटल हीना इंटरनॅशनल के सामने स्थित संग्राम होटल -/उ हॉल, जालना रोड, बीड में आयोजित किया गया है।

कार्यक्रम में बीड जिला परिषद के वरिष्ठ सहायक यूसुफ पठान विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे, जबकि साउंड सिस्टम की जिम्मेदारी हमेशा की तरह कृष्णा पांगरे निभाएंगे।

अतः सभी संगीतप्रेमी श्रोताओं से अनुरोध है कि वे बड़ी संख्या में इस आयोजन में शामिल होकर कार्यक्रम को सफल बनाएं, ऐसा आह्वान आयोजक और गायक एम.एम. शेख तथा पत्रकार एस.एम. यूसुफ ने किया है।

दैनिक भारत की तामीर अखबार के मालिक, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक काजी मखदूम शफीउद्दीन ने आरएम प्रिंटरर्स, बार्शी रोड, बीड 431122 महाराष्ट्र में मुद्रित कर के दैनिक तामीर, नगर परिषद परिसर, बशीर गंज, बीड, महाराष्ट्र कार्यालय से प्रकाशित किया है। मोबाइल : 9270574444 ईमेल : hinditameer@gmail.com वेबसाइट : www.dailytameer.com

daily Bharat ki tameer newspaper owner printer publisher editor Quazi makhdoom shafiuddin has printed at RM printers barshi road beed 431122 Maharashtra at published at office daily tameer nagar parishad complex Bashir gunj beed Maharashtra. Mobile : 9270574444 Email : hinditameer@gmail.com Website : www.dailytameer.com